रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 9 जनवरी, 1988/ 19 पौष, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, 30*th December*, 1987

No. 1-40/87-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, "The Himachal Pradesh

Appropriation (No. 5) Bill, 1987 (Bill No. 23 of 1987) having been introduced on the 30th December, 1987, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

L. S. KASHYAP,
Secretary.

1987 का विधेयक संख्यांक 23.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1987

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 1987 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए 34,58,72,307 रुपए की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धन-राशियां, जिनका योग 34,58,72,307 रुपए (चौंतीस करोड़, अठावन लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ सात रुपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1987-88 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रु0	रु0	रु0
2	राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद्	(राजस्व)	7,00,000	6,81,000	13,81,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	2,48,000	80,268	3,28,268
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	15,95,500	7,81,000	23,76,500
		(पूंजी)	7,36,000	—	7,36,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	56,80,000	—	56,80,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	—	18,400	18,400
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	90,93,000	1,05,480	91,98,480
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	8,18,000	70,000	8,88,000
		(पूंजी)	8,52,000	—	8,52,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	1,05,84,000	1,10,000	1,06,94,000
10	लोक निर्माण	(पूंजी)	7,00,000	—	7,00,000
11	कृषि	(राजस्व)	3,48,48,000	—	3,48,48,000
14	पशु पालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	45,84,000	48,414	46,32,414
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	33,88,000	—	33,88,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	3,20,54,000	—	3,20,54,000
		(पूंजी)	30,00,000	11,763	30,11,763
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	2,92,400	—	2,92,400
19	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	2,24,65,000	11,684	2,24,76,684
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	1,92,00,000	250	1,92,00,250
22	खाद्य और भण्डारण	(राजस्व)	9,54,00,000	—	9,54,00,000
		(पूंजी)	4,00,000	—	4,00,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	50,000	—	50,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	35,00,000	—	35,00,000
		(पूंजी)	31,76,000	—	31,76,000
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	2,79,88,098	—	2,79,88,098
		(पूंजी)	1,65,50,000	—	1,65,50,000
29	वित्त	(राजस्व)	4,08,78,000	—	4,08,78,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	5,00,000	—	5,00,000
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	29,20,000	59,050	29,79,050
		(पूंजी)	16,95,000	—	16,95,000
		जोड़	34,38,94,998	19,77,309	34,58,72,307
		(राजस्व)	31,62,85,998	19,65,546	31,82,51,544
		(पूंजी)	2,76,09,000	11,763	2,76,20,763

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
30 दिसम्बर, 1987.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाइल सं0 फिन-ए-सी-(2) 20/87-II]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1987 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

Bill No. 23 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1987

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 1988.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Act, 1987.

Issue of a further sum of Rs. 34,58,72,307 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 34,58,72,307 (Thirty-four crores, fifty-eight lakhs, seventy-two thousand, three hundred and seven rupees) towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year 1987-88 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	7,00,000	6,81,000	13,81,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	2,48,000	80,268	3,28,268
4	General Administration	(Revenue)	15,95,500	7,81,000	23,76,500
		(Capital)	7,36,000	—	7,36,000
5	Land Revenue	(Revenue)	56,80,000	—	56,80,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	—	18,400	18,400
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	90,93,000	1,05,480	91,98,480
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	8,18,000	70,000	8,88,000
		(Capital)	8,52,000	—	8,52,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	1,05,84,000	1,10,000	1,06,94,000
10	Public Works	(Capital)	7,00,000	—	7,00,000
11	Agriculture	(Revenue)	3,48,48,000	—	3,48,48,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	45,84,000	48,414	46,32,414
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	33,88,000	—	33,88,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	3,20,54,000	—	3,20,54,000
		(Capital)	30,00,000	11,763	30,11,763
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	2,92,400	—	2,92,400
19	Social Security and Welfare (including Nutrition)	(Revenue)	2,24,65,000	11,684	2,24,76,684
20	Rural Development	(Revenue)	1,92,00,000	250	1,92,00,250
22	Food and Warehousing	(Revenue)	9,54,00,000	—	9,54,00,000
		(Capital)	4,00,000	—	4,00,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	50,000	—	50,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	35,00,000	—	35,00,000
		(Capital)	31,76,000	—	31,76,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	2,79,88,098	—	2,79,88,098
		(Capital)	1,65,50,000	—	1,65,50,000
29	Finance	(Revenue)	4,08,78,000	—	4,08,78,000
30	Loans to Government Servants	(Capital)	5,00,000	—	5,00,000
31	Tribal Development	(Revenue)	29,20,000	59,050	29,79,050
		(Capital)	16,95,000	—	16,95,000
		Total	34,38,94,998	19,77,309	34,58,72,307
		(Revenue)	31,62,85,998	19,65,546	31,82,51,544
		(Capital)	2,76,09,000	11,763	2,76,20,763

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 30th December, 1987.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C (2) 20/87-II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 5) Bill, 1987, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।